मेरा मास्क आपकी रक्षा करता है,

सभी के लिए मास्क
आपका मास्क मेरी रक्षा करता है

सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

कोरोना वायरस से भारत की लड़ाई में हम पूर्ण रूप से सहभागी हैं।
इस कठिन समय में अपनी जिम्मेदारी का पूर्णत: पालन करते हुए हमारा हरसंभव प्रयास है कि तथ्यों पर आधारित खबरें ही प्रकाशित हों।
हम स्व-अनुशासन में भी हैं और सरकार की ओर से जारी सभी नियमों का पालन भी हमारी पहली प्राथमिकता है।

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 2 DECEMBER TO 8 DECEMBER 2020 • VOLUME- 19 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay money after the visa

IELTS | STUDY ABROAD

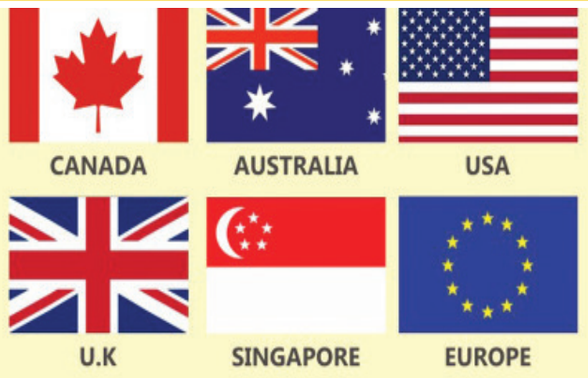

E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

बातचीत का ढकोसला बंद कर तीनों काले कानून खत्म करें सरकार: राहुल गांधी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार 'बातचीत का ढकोसला' बंद कर इन 'काले कानूनों' को खत्म करे।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि किसानों की आय आधी हो गई, लेकिन सरकार के 'मित्रों' की आय चौगुनी हो गई। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, ''मोदी सरकार, किसानों को जुमले देना बंद करें। बेईमानी अत्याचार बंद करें।

बातचीत का ढकोसला बंद करें। किसान-मज़दूर विरोधी तीनों काले क़ानून खत्म करें।''

उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए कहा, '' कहा गया था कि किसान की आय दुगनी होगी। लेकिन 'मित्रों' की आय हुई चौगुनी और किसान की हो गई आधी।'' राहुल गांधी ने आरोप लगाया, ''यह झूठ की, लूट की, सूट-बूट की सरकार है।'' उल्लेखनीय है कि नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 35 किसान संगठनों की चिंताओं पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंगलवार को हुई उनकी लंबी बैठक बेनतीजा रही। इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के निकट पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसान बोले- विशेष संसद सत्र बुलाकर तीनों कानून रद्द हों, हमें छोटी कमेटी मंजूर नहीं

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

सरकार के साथ कल चली तीन घंटे की बेनतीजा बातचीत के बाद किसानों ने आज फिर साफ किया कि तीनों कानून वापस किए जाएं. दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार लंबी चर्चा करके टरकाने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही किसानों ने एक बार फिर दोहराया कि छोटी कमेटी नहीं बनेगी। किसान नेता ने कहा- केंद्र से बातचीत के लिए किसानों की छोटी कमेटी नहीं बनेगी। हम सात या दस पेज का मसौदा सरकार को भेजेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानून को रद्द करे। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी कहा, अगर केंद्र ने जल्दी हमारी बात ना मानी तो किसान सख्त

कदम उठा सकते हैं. बगावत जैसी स्थिति उत्पन ना हो इसलिए सरकार किसानों की मांग जलद पूरी करें।

कानून रद्द नहीं हुए तो दिल्ली को चारो तरफ से बंद कर देंगे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, केंद्र कानून निरस्त नहीं करता तो दिल्ली को चारों तरफ से बंद कर दिया जाएगा। मोदी की भाषा ही उनके अफसर और मंत्री बोल रहे हैं। क्या किसान अनपढ़ हैं ? क्या कृषि के फायदा नुकसान किसान नहीं जानता? एक दिन का संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ेगा। वर्ना साल लगे या छ: महीने लगे यह आंदोलन चलता रहेगा। बता दें कि कल सरकार ने किसानों के साथ बैठक में एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था। कमेटी का फैसला आने तक किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की गई थी। जिसे किसानों ने नकार दिया है. इसके बाद बुधवार को सरकार और किसानों के बीच एक दौर की और बातचीत होगी।

किसानों के समर्थन में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की धमकी

किसानों के समर्थन में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा, किसान आंदोलन के चलते अगर कल शाम तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता या किसान अपना आंदोलन वापिस नहीं लेंगे तो आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के पूर्ण बंद के आवाहन का हमारी संस्थाएँ भी पूर्ण रूप से समर्थन करेंगी। बता दें कि अगर ट्रांसपोर्ट की हड़ताल होती है तो राजधानी दिल्ली में फल, सब्जी और दूध की किल्लत हो सकती है।

पंजाब: फलों के दाम पर पड़ रहा किसान आंदोलन का असर, आसमान छू रही हैं कीमतें

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

किसान आंदोलन के कारण पंजाब में फलों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय इंटरनेशनल फलों की कीमत घरेलू बाजार में बढ़ गई है आम तौर पर यह वह वक्त होता है, जिस समय फल सबसे सस्ता होता है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के कारण फलों की कीमतें आसमान छूह रही हैं। व्यापारी परेशान हैं क्योंकि पहले कोरोना वायरस के कारण काम नहीं था। उसके बाद अब किसानों के प्रदर्शन के कारण रेट बढ़ गए हैं। अगर ग्राहकों की बात की जाए तो मंडी में ग्राहक बिल्कलु नहीं हैं। आढ़तियों का कहना है कि किसान आंदोलन का हल सरकार जल्द करे, ताकि फलों की मंडी में बाहर के फल की किल्लत न हो।

मंडी में ग्राहक बिल्कुल नहीं हैं और ज्यादातर किसान और परिवार प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं, जिसका भी प्रभाव व्यापार पर पड़ रहा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को जल्द किसानों का हल निकालना चाहिए।

चीन में अनाज का संकट, कई दशकों में पहली बार भारत से खरीद रहा चावल

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

चीन इस वक्त अनाज के संकट का सामना कर रहा है. ऐसे में करीब तीन दशक में ऐसा पहली बार है जब चीन ने भारत से चावल का आयात शुरू किया है. भारतीय उद्योग अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रायटर्स को बताया कि अनाज की आपूर्ति कम होने और भारत की तरफ से कीमत में छूट के ऑफर के बाद ऐसा किया गया.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है जबकि चीन सबसे बड़ा आयातक. बीजिंग सालाना करीब 40 लाख टन चावल का आयात करता है लेकिन वह गुणवत्ता के मुद्दे का हवाला देकर अब तक भारत से खरीदने से बचता रहा है. ऐसे में चीन की तरफ से भारत से चावल खरीदने का यह फैसले ऐसे वक्त पर लिया गया है जब दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के चलते स्थिति बेहत तनावपूर्ण बनी हुई हैं।

राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रसिडेंट बी.वी कृष्ण राव ने कहा- पहली बार चीन ने चावल की खरीद की है। वह भारतीय अनाज की गुणवत्ता को देखकर अगले साल इसे और ज्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय व्यापारियों ने दिसंबर-फरवरी के लिए 3 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से 1 लाख टन चावल का निर्यात करने का अनुबंध किया है। इंडियन ट्रेड ऑफिशियल के मुताबिक, चीन के पारंपरिक चावल आपूर्तिकर्ता देश जैसे- थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार और पाकिस्तान के पास निर्यात के लिए सीमित मात्रा में अनाज है और वे भारत की तरफ से तय कीमतों के मुकाबले प्रति टन 30 डॉलर ज्यादा की मांग कर रहे हैं।

पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर सरकार ने चीन के साथ किया ये समझौता

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की सरकार ने 1.35 अरब डॉलर की अनुमानित लागत से 700 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए चीन की कंपनी और स्थानीय नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी से करार किया है। यह परियोजना महत्वकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) का हिस्सा है। डॉन अखबार में बुधवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक चीन की गेझोउबा समूह और स्थानीय साझेदार 'लारैब ग्रुप पाकिस्तान' पीओके के साधनोटी जिले में झेलम नदी पर प्रस्तावित 'आजाद पट्टन हाड्रोपॉवर प्रोजेक्ट' के साझेदार हैं। अखबार के मुताबिक परियोजना के लिए चीन विकास बैंक, चीन निर्माण बैंक, औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक चीन और बैंक ऑफ चाइना का समूह वित्त मुहैया कराएग।

शिवसेना की मांग, मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाए केन्द्र

■ मुंबई/ब्यूरो

शिवसेना ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिये बुधवार को केन्द्र सरकार से मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये कहा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया है कि यह ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है।

संपादकीय में कहा गया है, केन्द्र को ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के वास्ते मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये अध्यादेश लाना चाहिये।

शिवसेना के मुंबई-दक्षिण विभाग के प्रमुख पी सकपाल ने मुसलमान बच्चों के बीच अजान पढ़ने की प्रतियोगिता कराने का सुझाव दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था।

इस विवाद के बीच संपादकीय में यह टिप्पणी की गई है। संपादकीय में कहा गया है कि शिवसेना नेता

द्वारा अजान की प्रशंसा किये जाने की भाजपा द्वारा आलोचना किया जाना ठीक वैसा ही है, जैसा दिल्ली की सीमाओं पर (नये कृषि कानूनों के खिलाफ) प्रदर्शन कर रहे किसानों को पाकिस्तानी आतंकवादी कहना। लेख में कहा गया है प्रदर्शनकारी किसानों में अधिकतर लोग वे हैं जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं या जिनके बच्चे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।

सामना के मराठी संस्करण में कहा गया है, किसानों को आतंकवादी कहने वालों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ट्रोल करने वालों को लगता है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, लेकिन ईद के पकवान खाते हुए उनकी (भाजपा नेताओं) तस्वीरों पर कोई कुछ नहीं बोलता। संपादकीय में कहा गया है, हम इसे इसलिये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते क्योंकि देश के 22 करोड़ मुसलमान भारतीय नागरिक हैं।

किसान आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी, राजस्थान-हरियाणा सीमा पर भी जुटने लगे किसान

■ जयपुर/ब्यूरो

केन्द्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध की सुगबुगाहट अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगी है। इसी कड़ी में अलवर जिले में हरियाणा सीमा पर बुधवार को राजस्थान के किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में राजस्थान के किसानों ने हरियाणा सीमा पर जुटना शुरू कर दिया है। यहां किसानों की एक महापंचायत आयोजित होगी। उसके बाद किसान आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। जाट ने अलवर में हरियाणा सीमा पर संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्र सरकार से कृषि कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर उसकी

गारंटी का प्रावधान जोड़ने की मांग की है। उन्होंने कहा, ''इन कृषि कानूनों में विदेशी निवेशको को रिझाने की चिंता की गई है, उनकी प्रसन्नता को देखते हुए इन्हें पारित किया गया है, इनसे जो बडे पूंजी वाले हैं उनको कृषि उपजो के व्यापार में एकाधिकार प्राप्त होगा, जिन्हें एकाधिकार प्राप्त होगा वे कृषि उत्पादों का दाम कम से कम चुकायेंगे और उपभोक्ता की जेब से अधिक से अधिक दाम वसूलेंगे और इस कारण से किसान जो उत्पादन करने वाला है और गरीब उपभोक्ता जो खाने वाला है, दोनो लूटेंगे।''उन्होंने कहा, ''संविदा खेती में किसान खुद के खेत में ही मजदूर बन जायेगा। हिन्दुस्तान का किसान जो खेती में निपुण है उसको ये कह रहे है कि नहीं-नहीं आप तो जैसे कंपनी कहे वैसी खेती करो और बाद में जब आपकी उपज पैदा हो जायेगी तब उसका चयन कंपनियां करेगी।''

उन्होंने कहा,'' आप क्या चाहते हैं जो किसानों के लिये हितकर हो?'' इस सवाल का जवाब देते हुए रामपाल जाट ने कहा, ''सबसे अच्छा तो यह है कि भारत सरकार इन कानूनों को वापस ले ले.. यदि उनको यह लगे कि नहीं यह तो हमारी नाक का बाल बन गया क्योंकि हमने विदेशी निवेशकों से वादा कर लिया.. उनको यदि यह लगे तो एक बीच का रास्ता निकाल ले। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून जोड दें।

सुशील मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन, सीएम नीतीश भी रहे मौजूद

■ पटना/ब्यूरो

भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजग के प्रत्याशी के तौर पर बुधवार को नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान के निधन की वजह से इस सीट पर चुनाव हो रहा है। पटना आयुक्त कार्यालय में राज्यसभा उपचुनाव के लिए राजग प्रत्याशी सुशील कुमार मोदी के नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राजग के कई नेता उपस्थित थे। पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल के समक्ष सुशील मोदी के नामांकन के बाद पत्रकारों से नीतीश कुमार ने कहा, आज हम सब सुशील कुमार मोदी जी को बधाई देने के लिए आए हैं। इन्होंने बिहार की काफी सेवा की है। ये पहले से ही लोकसभा, बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और अब राज्यसभा के भी सदस्य बनने जा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो संसद के दोनों सदनों और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य रहें। इसलिए इन्हें विशेष तौर पर बधाई। बिहार राजग सरकार में अपने मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री रहे सुशील के बारे में नीतीश ने कहा, मुझे खुशी है कि हमलोगों ने साथ काम किया है लेकिन हर एक पार्टी का अपना निर्णय होता है। ये अब राज्यसभा के लिये निर्वाचित होने वाले हैं। इन्हें सभी लोग बधाई देने के लिए आए हैं। केंद्र सरकार के

सहयोग का लाभ बिहार को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सुशील के नामांकन के समय उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, राजग के अन्य घटक दल के नेता वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष कुमार सहित बिहार सरकार के अन्य मंत्री मौजूद थे। राज्यसभा की इस सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तीन दिसंबर को आखिरी तारीख है। सात दिसंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है व 14 दिसंबर को मतदान होगा।

केंद्र में राजग के घटक दल लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवन के निधन के कारण यह सीट खाली हुई है। रामविलास ने अपने कैबिनेट सहयोगी रविशंकर प्रसाद के पटना साहिब लोकसभा सीट जीतने के बाद पिछले साल इस सीट के लिए हुए उपचुनाव में निर्विरोध चुने गये थे। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में राजग में शामिल जदयू के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को अस्वीकार्य बताते हुए अकेले अपने बलबूते चुनावी मैदान में उतरी लोजपा के प्रमुख और रामविलास के पुत्र चिराग पासवान ने राज्यसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा तवज्जो नहीं दिये जाने के बाद शनिवार को कहा था कि यह भगवा पार्टी की सीट है जो इस बात का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह किसे चुनाव मैदान में उतारना चाहती है।

दखल

सवालों में फिलस्तीन का भविष्य

बदलती परिस्थितियों में फिलस्तीन का भविष्य इजराइल की उस मंशा के अनुसार नजर आ रहा है, जिसके संकेत पूर्व में ही मिल चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का विश्वास रहा है और वे कहते भी आए हैं कि फिलस्तीनी समस्या के समाधान को परे रख कर भी अरब देशों के साथ शांति समझौते किए जा सकते हैं। मध्यपूर्व अब पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहा है और अरब देशों के लिए फिलस्तीन नीतिगत और निर्णायक मुद्दा नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है और विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हितों के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। 1947 से विश्व राजनीति में उथल-पुथल मचाने वाले इजराइल और फिलस्तीन का जमीनी विवाद अब इन दो राष्ट्रों तक ही सीमित रहने के संकेत मिलने लगे हैं। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'डील आफ द सेंचुरी' के दांव में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन ने जब हाथ मिलाया था, तभी यह साफ हो गया था कि मध्यपूर्व अब पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ रहा है और अरब देशों के लिए फिलस्तीन नीतिगत और निर्णायक मुद्दा बना नहीं रह सकता। दरअसल, 1947 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा फिलस्तीन को स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र और अरब राष्ट्र में बांटने की सिफारिश के बाद इस इलाके में संघर्ष का नया दौर शुरू हो गया था।

फिलस्तीन को मुस्लिम और अरब अस्मिता से जोड़ने वाले ज्यादातर अरब देश इस नीति पर अडिग माने जाते थे कि वे इजराइल के साथ रिश्ते तभी सामान्य करेंगे, जब वह फिलस्तीन के साथ जारी अपने विवाद का निबटारा कर लेगा। लेकिन 1947 से लेकर 2020 तक मध्यपूर्व की भू-रणनीतिक स्थितियों में भारी बदलाव आए। इजराइल को रणनीतिक रूप से घेरने वाले देश आंतरिक अशांति और राजसत्ता की अपनी मजबूरियों से जूझ रहे हैं। इजराइल के उत्तर में लेबनान और पूर्व में सीरिया है। ये दोनों देश गृहयुद्ध से त्रस्त हैं। जबकि दूसरे पड़ोसी जार्डन और मिस्र 1967 के इजराइल-अरब युद्ध के बाद यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर खामोश हैं। इन सबके बीच इजराइल को मध्यपूर्व से खत्म कर अरब राष्ट्रवाद की अगुवाई के स्वप्न ने ही इस्लामिक दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। इजराइल-फिलस्तीन विवाद की परछाई में शिया बाहुल्य ईरान ने लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला को भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद देकर इजराइल पर हमला करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया, वहीं सुन्नी बाहुल्य सऊदी अरब ने फिलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को हथियार देकर इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की।

इस्लामिक दुनिया में बादशाहत कायम रखने के लिए ईरान और सऊदी अरब इजराइल को निशाना बनाते-बनाते आपसी हितों के लिए कालांतर में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन गए। इजराइल को घेरने के साथ-साथ ईरान मध्यपूर्व के देशों में शिया प्रभाव जमाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने लगा था। सुन्नी बहुल सऊदी अरब को बर्दाश्त नहीं था। इसका प्रभाव मध्यपूर्व से लेकर यूरोप तक पड़ा और सीरिया, इराक, लीबिया, लेबनान, यमन से लेकर तुर्की सहित कई देश प्रभावित हुए। मध्यपूर्व पिछले कई सालों से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों में ईरान समर्थित सेना इन देशों में स्थित सुन्नी प्रशासन के खिलाफ विद्रोहियों को हथियार और प्रश्रय दे रही है।

ईरान एक मजबूत शिया बाहुल्य देश है जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की आंखों की किरकिरी होने के बाद भी अपने मजबूत राष्ट्रवाद के बूते जिंदा और आबाद है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड सीरिया और इराक में कट्टरपंथी सुन्नी एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं और यमन के हूती विद्रोही शिया प्रभाव को उस इलाके में काबिज रखे हुए हैं। दूसरी ओर लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी संगठन इजराइल की नाक में दम किए हुए है। आर्थिक जरूरतें बढ़ने, तेल का घाटा दूर करने और ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए सऊदी अरब ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) का दांव खेला था, जिससे सीरिया, इराक और ईरान तबाह हो जाएं, इन देशों के तेल भंडार नष्ट हो जाएं और वह तेल की दुनिया का बादशाह हो जाए। शिया-सुन्नी संघर्ष और आर्थिक फायदों के लिए यह समूचा क्षेत्र ही अस्थिर हो गया। ऐसे में इजराइल के धुर विरोधी देश अब फिलस्तीन से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की फिक्र कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि मध्य पूर्व में रणनीतिक साझेदारी में अरब की अगुवाई का सपना देखने वाला सऊदी अरब अब इजराइल का हमराह बन रहा है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने कभी की होगी।

इजराइल अब मध्यपूर्व का सबसे बड़ा रणनीतिक खिलाड़ी बन कर अरब से संबंधों की जो नई इबारत गढ़ रहा है, उससे फिलस्तीन सहित वैश्विक कूटनीतिक में भारी बदलाव होने की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। साल 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा सरकार ने ईरान से एक परमाणु समझौता किया था, जिसके तहत साल 2016 में अमेरिका और अन्य पांच देशों से ईरान को तेल बेचने और उसके केंद्रीय बैंक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार की अनुमति मिली थी। ओबामा के इस समझौते को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने की कोशिशों के तौर पर देखा गया था। सऊदी अरब अमेरिका के इस कदम से नाराज था और इसका प्रभाव ओबामा के जाते ही दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति और आर्थिक हितों को प्राथमिकता में रख कर आगे बढ़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही इस समझौते को बेकार बता कर अपने कदम वापस खींच लिए। जबकि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश ईरान से समझौते का पालन करना चाहते थे। यूएई और सऊदी अरब जैसे देश यह भलीभांति जानते हैं कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों का मतलब है कि उन्हें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित अमेरिका का भरपूर समर्थन मिलेगा और इससे ईरान पर अभूतपूर्व दबाव पड़ेगा।

मध्यपूर्व की राजनीति को तेल की अतंरराष्ट्रीय राजनीति से अलग कर देखना असंभव है। अमेरिका की नजर ईरान के तेल कुओं पर है और वह उस पर दबाव डालने के लिए प्रतिबद्धता दिखाता रहा है जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में उतार-चढ़ाव पर अमेरिका का नियंत्रण बना रहे। इजराइल और यूएई दोनों ही ईरान को अपना साझा दुश्मन मानते हैं और उन्हें लगता है कि इस तरह का समझौता करके वे ईरान के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इजराइल सऊदी अरब से खुफिया जानकारियां साझा करता रहा है और वह शिया देश ईरान के दुश्मनों को आधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरण बेचने के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। इजराइल के यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से मजबूत होते संबंधों के बाद यह संभावना बढ़ गयी है कि अरब क्षेत्र में उसे मान्यता और वैधता मिलेगी और इससे दूसरे अरब देश भी इजराइल से हाथ मिला सकते हैं। बदलती परिस्थितियों में फिलस्तीन का भविष्य इजराइल की उस मंशा के अनुसार नजर आ रहा है जिसके संकेत पूर्व में ही मिल चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का विश्वास रहा है और वे कहते भी आए हैं कि फिलस्तीनी समस्या के समाधान को परे रख कर भी अरब देशों के साथ शांति समझौते किए जा सकते हैं।

फिलस्तीन की स्थापना के लिए वर्षों से राजनयिक और सैनिक समर्थन देने वाले इस्लामिक देशों के मजबूत स्तंभों के इजराइल के साथ चले जाने से रणनीतिक मायने बदल गए हैं। इससे ईरान और तुर्की के साथ सऊदी अरब की प्रतिद्वंद्विता बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसके दूरगामी परिणाम इस्लामिक देशों में आपसी संघर्ष को बढ़ा सकते हैं। बहरहाल फिलस्तीन के मुद्दे को पीछे छोड़ कर अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध वैश्विक कूटनीति को नई दिशा देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

विचार

चीन की उकसावे की रणनीति

लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने अब चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। यह हरकत दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाएगी। साथ ही शांति वार्ता में रुकावट भी बन जाएगी।

लद्दाख में लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन हमेशा उकसावे वाली रणनीति अपना रहा है। एलएसी पर निर्माण कार्य के बाद अब चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। अगले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। चीन कह रहा है कि बांध बनने से दक्षिण एशियाई देशों से सहयोग के रास्ते खुलेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने चीन से ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते का पालन करने को कहा है। चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र पर प्रोजेक्ट बनाने की बात कही है। इस बड़े बांध की तैयारी ने भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही देश ब्रह्मपुत्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चीन ने इन चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह दोनों देशों के हितों का ध्यान रखेगा। भारत ने चीन के इस कदम का विरोध किया है। चीन की इस तरह की गतिविधियां उसकी युद्ध की मानसिकता और तैयारियों का संकेत हैं। इससे यह जाहिर होता है कि वह किसी न किसी बहाने भारत को उकसा कर लड़ाई छेड़ने की फिराक में है। इस साल मई से लेकर अब तक के घटनाक्रम से भी इसकी पुष्टि होती है।

मई महीने में सीमा पर घुसपैठ और मारपीट की घटनाओं की परिणति 15-16 जून की आधी रात गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमले के रूप में देखने को मिली, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद अगस्त के आखिरी हफ्ते में भी चीनी सैनिकों ने आक्रामक रुख दिखाया, जिसे भारतीय सैनिकों की सजगता से नाकाम कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ समय में भारत को लेकर चीन ने जो रुख दिखाया है, उसका दोनों देशों के संबंधों बुरा असर पड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरों से उम्मीद बंधी थी कि अब दोनों देशों के बीच रिश्तों के नए युग की शुरुआत होगी और सीमा विवाद हल करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। पहली बार चीनी राष्ट्रपति सितंबर 2014 में भारत आए थे और दूसरी बार पिछले साल अक्टूबर में। लेकिन भारत की उम्मीदों पर पानी फिरने में साल भर भी नहीं लगा।

मई से ही चीन ने लद्दाख क्षेत्र में एलएसी पर जिस तरह की घुसपैठ और सैन्य गतिविधियां जारी रखी हुई हैं, उससे तो कहीं नहीं लगता कि चीन भारत का अच्छा दोस्त और पड़ोसी हो सकता है। ऐसे में हैरानी पैदा करने वाली बात यह है कि एलएसी पर चीन जो कर रहा है, क्या वही रिश्तों का नया युग है! विदेश मंत्री ने खुद इस हकीकत को स्वीकार किया है कि पैंगोंग में जून में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले ने तीस साल से चले आ रहे सामान्य रिश्तों को खत्म कर डाला। इससे न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर, बल्कि जनता के स्तर पर भी गहरा असर पड़ा है। मुश्किल यह है कि सीमा पर शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए भारत-चीन के बीच अब तक जो करार हुए हैं, चीन ने उनकी धज्जियां उड़ाई हैं।

किसानों का जीवन होता खुशहाल

कृषि मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर सरकारी, अंतरराष्ट्रीय और निजी तकनीकी एजेंसियों के साथ पहल की है। उम्मीद है कि अगले एक से दो वर्षों में उपज अनुमान के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा। इससे फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और लंबे समय तक छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री की यह योजना किसानों का जीवन बदलने वाली साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) पूरे फसल चक्र में सभी प्राकृतिक खतरों से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया जोखिम को कम करने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। किसानों के सबसे कम प्रीमियम देने और फसल का उच्चतम मूल्य, बीमा से सुरक्षित करने वाली यह पहली योजना है। देश में आईआरडीएआई द्वारा पंजीकृत सभी सामान्य बीमा कंपनियां, जिनकी गांवों में अच्छी-खासी मौजूदगी है, को योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वर्तमान में, इरडा में पंजीकृत सभी 5 सरकारी कंपनियां और 13 निजी कंपनियां पैनल में हैं। कंपनियों की संख्या बढ़ाने के पीछे मूल विचार ग्रामीण क्षेत्र में उनके बढ़ते हुए नेटवर्क और योजना के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाना है।

यह योजना अपने कार्यान्वयन के 5वें वर्ष में है और कार्यान्वयन में आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए हाल ही में इसमें सुधार किए गए हैं, जिसमें सभी किसानों के लिए इसे स्वैच्छिक बनाना और सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। योजना से लाभ लेने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों और बीमा कंपनियों की भागीदारी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। योजना के कार्यान्वयन के पहले 3 वर्षों में, जिसका पूरा डेटा उपलब्ध है, राष्ट्रीय स्तर पर सभी बीमा कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से दावों का अनुपात 89 फीसदी रहा। इसका मतलब यह है कि बीमा कंपनियों की ओर से प्रीमियम के रूप में इकट्ठा किए गए हर 100 रुपये के लिए 89 रुपये का दावों के रूप में भुगतान किया गया। बीमा कंपनियों पर आमतौर पर फिर से बीमा करने और प्रशासनिक खर्चों के लिए 10-12 प्रतिशत खर्च आता है। इस प्रकार से पहले 3 वर्षों में अच्छे मॉनसून के बावजूद बीमा कंपनियों को मुश्किल से कोई नुकसान हुआ है।

किसी भी भारी जोखिम वाली योजना का मूल्यांकन कम से कम 5 साल पूरा होने और राष्ट्रीय (कुल) स्तर पर किया जाना चाहिए। यह तर्क देना कि किसी विशेष कंपनी में किसी विशेष सीजन में ज्यादा या कम हानि अनुपात था, कंपनी या योजना के प्रदर्शन को देखने का सही तरीका नहीं है। खरीफ 2019 का मौसम विशेष रूप से फसल के हिसाब से एक अच्छा मौसम था लेकिन बेमौसम भारी बारिश ने कटाई की गई फसलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में पर्याप्त दावों का भुगतान हुआ, जहां क्रमशः दावा अनुपात 121 फीसदी और 213 फीसदी था। किसानों को दावों के भुगतान के लिए राज्य द्वारा बीमा कंपनियों को सीसीई डेटा समय पर साझा करने और प्रीमियम सब्सिडी के अपने शेयर को जारी करने की आवश्यकता होती है। और कुछ मामलों में फसल कटाई प्रयोग डेटा साझा/राज्य सब्सिडी जारी करने में देरी के चलते आगे किसानों के दावों का भुगतान करने में देरी हुई है।

निजी बीमा कंपनियों समेत बीमा कंपनियों द्वारा कम दावा अनुपात और लाभ अर्जित करने को लेकर आलोचना की गई जो अधूरे डेटा पर आधारित है और इस कारण योजना की निराधार आलोचना होती है। बाद में जब सीजन के लिए पूरा डेटा उपलब्ध हो गया तो दावा अनुपात काफी बढ़ गया। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डेटा में अंतर की समस्या का समाधान करने के लिए कृषि मंत्रालय हर महीने सीजन वार डेटा जारी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेषज्ञ सबसे ताजा आंकड़ों के आधार पर योजना के प्रदर्शन का पूरा विश्लेषण कर सकें। तीन साल की अवधि (2016-17 से 2018-19) के लिए सरकारी और निजी बीमा कंपनियों के लिए डेटा का विश्लेषण करने पर, जिसके लिए अधिकांश डेटा प्राप्त हो गया है, सरकारी और निजी कंपनियों के लिए दावा अनुपात क्रमशः 98.5 फीसदी और 80.3 फीसदी है। खरीफ 2019 के लिए गुजरात, झारखंड और कर्नाटक से सीसीई डेटा प्राप्त नहीं हुआ है और रबी 2019-20 का डेटा आधा दर्जन राज्यों से लंबित है। ऐसे में 2019-20 के लिए निजी समेत कंपनियों के लिए अंतिम दावा अनुपात लंबित डेटा के मिलने के बाद बढ़ सकता है।

खरीफ 2020 से प्रभावी योजना के तहत बीमा कंपनियों को तीन साल की अवधि के लिए काम आवंटित करने का प्रावधान किया गया है, जो उच्च/निम्न दावा अनुपात के सीजन के संदर्भ में किसी भी अस्थिरता को औसत रूप में लाएगा। इसके साथ ही प्रीमियम जुटाने और बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए दावों के संदर्भ में योजना के विश्लेषण के लिए एक आदर्श अवधि उपलब्ध कराएगा। प्रीमियम के प्राइमरी ड्राइवर निम्नतम स्तर पर ऐतिहासिक उपज डेटा की अनुपलब्धता है और मानवीय त्रुटियों के कारण उपज डेटा की गणना और रिकॉर्डिंग में विसंगतियां हैं। सैटेलाइट इमेजरी, मौसम संबंधी आंकड़े और मिट्टी की नमी के आंकड़े को शामिल करते हुए एक मजबूत अंकगणितीय मॉडल के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित उपज के आकलन से प्रीमियम की दरों को कम करने और योजना के कार्यान्वयन को स्थिर किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर प्रमुख सरकारी, अंतरराष्ट्रीय और निजी तकनीकी एजेंसियों के साथ पहल की है और उम्मीद है कि अगले एक से दो वर्षों में उपज अनुमान के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा। इससे फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और लंबे समय तक छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार ने 2016 में शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान को बीमा के जरिए कवर किया जाता है। इसमें सूखे, बाढ़, तूफान या ओलावृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कवर किया गया है। इस योजना में हाल में कुछ सुधार किया गया है जिनकी किसान की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी। जिसके बाद ही कई किस्म की शिकायतें आने के बाद योजना बदलाव हुए हैं। योजना में अब किसानों को अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक बीमा लेने की सुविधा मिली है। यानि कि किसान चाहे तो सूखे, बाढ़, तूफान या ओलावृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के लिए अलग-अलग बीमा ले सकते हैं। अगर किसान को लगता है कि उसकी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ और सूखे से हो सकता है तो वह दोनों के लिए एकसाथ बीमा या अलग-अलग बीमा ले सकते हैं। यानि कि किसान रिस्क कवर ले सकता है।

नुकसान की भरपाई के आकलने के लिए कृषि क्षेत्र का सैटेलाइट के जरिए निरीक्षण किया जाता है और इसके बाद ही बीमा कवर की राशि तय की जाती है। किसानों को प्रीमियम के तौर पर इंश्योर्ड राशि का दो फीसद (खरीफ फसलों के लिए) और 1.5 प्रतिशत (रबि फसलों के लिए) देने का प्रावधान है। इस योजना के शुरुआत में सभी लोन लेने वाले किसानों के लिए इस योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस लेना अनिवार्य किया गया था लेकिन नए बदलाव के तहत अब यह स्वैच्छिक कर दिया गया है।

ट्विटर

चीन लंबे समय से भारत के साथ उकसावे वाली रणनीति पर काम कर रहा है और हिमालय क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। यह दोनों देशों के लिए गलत है।

राजा कृष्णमूर्ति, अमेरिकी सांसद

चीन की किसी की हिमाकत का भारत खुलकर जवाब देगा। हमारी नीति शांति की है, इसीलिए हम युद्ध से बचना चाह रहे हैं। मगर चीन इसे दूसरे अर्थ में ले रहा है।

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री

सत्यार्थ

महात्मा और डकैत

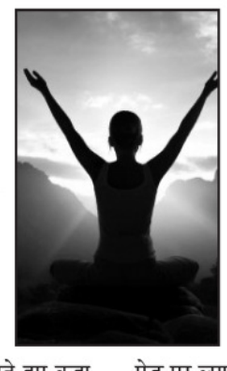

बहुत पुरानी बात है। एक दिन एक महात्माजी जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक डाकुओं का एक दल सामने आ गया। डाकुओं के सरदार ने कहा-जो भी माल तुम्हारे पास है, निकालकर रख दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। महात्माजी डाकू की धमकी से जरा भी नहीं घबराए, बल्कि उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि वह तो भिक्षा पर पलने वाले संन्यासी हैं, उनके पास कोई सामान कहां से आएगा। डाकुओं के सरदार ने अट्टहास करते हुए कहा कि उनके पास भले ही कुछ और न हो, मगर जान तो है ही, उसे ही ले लेते हैं। महात्माजी ने कहा-ठीक है, तुम मेरी जान ले लो, पर मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। डाकुओं के सरदार ने पहले कुछ सोचा फिर मान गया। उसने महात्माजी से पूछा कि वे क्या चाहते हैं? महात्माजी ने कहा-पेड़ से दो पत्ते तोड़ लाओ। डाकू पत्ते तोड़ लाया और महात्माजी को देने लगा। महात्माजी ने कहा-ये पत्ते मुझे नहीं चाहिए। तुम इन्हें वापस पेड़ पर लगा आओ। डाकुओं के सरदार ने हैरान होकर कहा-यह आप क्या कह रहे हैं। कहीं टूटे हुए पत्ते भी दोबारा पेड़ पर लग सकते हैं? इस पर महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा-यदि तुम टूटी हुई चीजों को जोड़ नहीं सकते, तो कम से कम उसे तोड़ो भी मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महात्माजी की बात सुनकर डाकू सरदार की आंखें खुल गईं और वह अपने साथियों के साथ हमेशा के लिए लूटपाट छोड़कर एक नेक इंसान बन गया। यह कथा डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की है। इसका संदेश यह है कि हम अगर दूसरों का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उनका बुरा करने से तो हर हाल में बचें।

लद्दाख में ठंड के चलते चीन की हालत खराब

चीनी सेना अग्रिम चौकियों पर हर रोज बदल रही है अपने सैनिक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पूर्वी लद्दाख में कड़ाके की ठंड के चलते चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की हालत अभी से खराब होने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि वे कब तक भारतीय जवानों के सामने इस ठंड में टिक पाएंगे। ठंड के मौसम में अनुभवहीन सैनिक रोजाना अग्रिम चौकियों पर जवानों को बदल रहे हैं, जबकि भारतीय सैनिक उसी लोकेशन में लंबे समय से तैनात हैं।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि हमारे सैनिक चीनी जवानों के मुकाबले लंबे समय तक वास्तविक नियंत्रण रेखा की अग्रिम चौकियों पर तैनात हैं। कड़ाके की ठंड और ऐसे इस मौसम के अनुभवहीन चीनी सैनिक के चलते चीन की तरफ से रोजाना सैनिकों को वहां से बदला जा रहा है। चीन के मुकाबले भारतीय सेना के जवानों को ऐसे मौसम से मुकाबला करने में बढ़त है, क्योंकि उनमें से कई पहले ही पूर्वी लद्दाख और सियाचीन जैसी अन्य चोटियों पर ड्यूटी कर चुके हैं।

रोजाना नए सैनिकों की तैनाती कर रहा चीन

सूत्रों ने बताया कि चीन की तरफ से सामरिक ऊंचाई वाली जगहों पर भारतीय जवानों के मुकाबले तैनात किए गए सैनिकों पर ठंड का असर देखा जा सकता है। एक तरफ जहां भारतीय जवान वहां पर ठहरे हुए हैं तो वहीं चीनी सैनिक रोजाना नए सैनिकों की तैनात कर पहले से तैनात सैनिकों को हटा रहा है। गौरतलब है कि मई से भी भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में विवाद शुरू हुआ है। चीन की तरफ से भारी हथियार और टैंक के साथ करीब 60 हजार सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा से लगते एलएसी पर तैनात कर दिया गया।

लोक जनशक्ति पार्टी नहीं लड़ेगी राज्यसभा चुनाव

पटना, (एजेंसी)। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजद का समर्थन लेने से इंकार कर दिया। चिराग ने राजद के समर्थन देने के प्रस्ताव को सधन्यवाद ठुकरा दिया। इसके साथ ही पासवान ने यह भी कहा कि अब उनकी पार्टी राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी।

लोजपा व दलित सेना के संस्थापक राम विलास पासवान के निधन के बाद रिक्त राज्यसभा की सीट पर चुनाव होना है। इसके लिए आरजेडी ने एलजेपी को प्रस्ताव दिया था कि अगर चिराग राज्यसभा चुनाव के लिए रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को मैदान में उतारते हैं, तो आरजेडी समर्थन देने को तैयार है। महागठबंधन के कई नेता प्रस्ताव लेकर चिराग से संपर्क कर रहे थे, किंतु चिराग ने इसको स्वीकारने से इंकार कर दिया है। लोजपा ने ट्वीट कर कहा कि लोजपा और दलित सेना के संस्थापक राम विलास पासवान के निधन से रिक्त सीट पर चुनाव है, राज्यसभा की यह सीट संस्थापक के लिए थी, जब पार्टी के संस्थापक नहीं रहे, तो यह सीट भाजपा किसको देती है यह उनका निर्णय है। पार्टी ने अन्य ट्वीट में कहा कि आरजेडी ने अपना समर्थन इस सीट पर लोजपा प्रत्याशी को करने की बात की है। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर लोजपा का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है।

मतदान की ललक

ब्यावर देवी को उनकी बहू प्रेम देवी ने राजस्थान में ब्यावर में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के दौरान वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचाया।

न्यूज

मुंबई से बॉलीवुड को कोई नहीं हटा सकता : पाटिल

कोल्हापुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि कोई भी मुंबई से बॉलीवुड को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सकता। श्री पाटिल मंगलवार को विधान परिषद के लिए हो रहे चुनाव के लिए मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। श्री पाटिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई से बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश ले जाने के बयान के संबंध में कहा कि बॉलीवुड को मुंबई से बाहर कोई नहीं ले जा सकता। जो सुविधा मुंबई में उपलब्ध है, ऐसी सुविधा और कहीं उपलब्ध नहीं है।

भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का किया गया अंतिम संस्कार

उदयपुर। राजस्थान में भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का मंगलवार को यहां अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्रीमती माहेश्वरी की अंतिम यात्रा रानी रोड स्थित मोक्षधाम पहुंची, जहां उनके बेटे प्रशांत ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनके परिजन एवं अंतिम संस्कार में शामिल अन्य लोगों ने पीपीई किट पहन रखी थी। इससे पहले श्रीमती माहेश्वरी के आवास पर उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला एवं राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी एवं अनीता भेदल तथा प्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

टीआरएस विधायक नोमुला नरसिम्हैया का निधन

हैदराबाद। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) विधायक नोमुला नरसिम्हैया का मंगलवार को यहां एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चौंसठ वर्षीय श्री नरसिम्हैया जाने-माने अधिवक्ता भी रहे। वह आंध्र प्रदेश के नाकरेकल सीट से से दो बाद विधायक निर्वाचित हुए थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री नरसिम्हैया के निधन से पार्टी और उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता को अपूरणीय क्षति हुई है। श्री राव ने दिवंगत विधायक के परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।

ट्रंप के कोविड-19 विशेष सलाहकार का इस्तीफा

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष सलाहकार (कोविड-19) स्कॉट एटलस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। फॉक्स न्यूज ने श्री एटलस की ओर से प्राप्त इस्तीफे की प्रति के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। पत्र में उन्होंने श्री ट्रंप के प्रयासों की प्रशंसा की है और आने वाले दिनों में निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यशील होने वाले प्रशासन को शुभकामनाएं दी है। श्री एटलस ने अपने पत्र में लिखा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दे रहा हूं रिपोर्ट के मुताबिक श्री एटलस ने गत अगस्त में विशेष सलाहकार का दायित्व संभाला था और अगले सप्ताह उनकी सेवा अवधि समाप्त होने वाली थी।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे!
कोरोना वायरस से सावधान रहे
क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं।
कोरोना को धोना हैं।

ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की मौत को लेकर बड़ा दावा

रिमोट नियंत्रित हथियार से की गई मोहसिन की हत्या

नई दिल्ली, (एजेंसी)। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजदेह की हत्या को लेकर एक नई बात सामने आई है। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन की हत्या के लिए ईरान ने इजरायल को दोषी ठहराया है। ईरान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके वैज्ञानिक की हत्या एक रिमोट नियंत्रित हथियार से की गई है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा प्रमुख अली शमखानी ने कहा है कि हमलावरों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया और वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख शमखानी ने कहा कि उनकी सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक उपाय किए गए थे, लेकिन दुश्मनों ने बिल्कुल नए तरीके का इस्तेमाल किया। इस हत्या को पेशेवर और विशेष तरीके से अंजाम दिया गया है। दुर्भाग्य से हमारे दुश्मन इसमें सफल रहे। यह बहुत ही जटिल मिशन था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। घटनास्थल पर कोई भी मौजूद नहीं था।

ईरानी खुफिया एजेंसियों को था हत्या की साजिश का अंदेशा

ईरानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को फखरीजादेह की हत्या की साजिश का अंदेशा पहले से ही था और इस तरह के हमले की आशंका भी पहले से ही थी। हालांकि इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। शुरुआत में ईरानी रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि फखरीजादेह की कार को कुछ बंदूकधारियों ने निशाना बनाया था और उसी दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। एडमिरल शमखानी ने कहा कि इस हत्या को अंजाम देने वालों का कुछ सुराग मिला है। उन्होंने कहा कि इसमें यहूदी शासन और मोसाद के साथ निर्वासित ईरानी विपक्षी समूह मुजाहिदीन-ए खाल्क (एमकेओ) निश्चित तौर पर शामिल रहा है। ईरान द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर इजरायल ने अपना पक्ष नहीं रखा है।

फखरीजादेह ने की थी परमाणु हथियार कार्यक्रम की शुरुआत

हत्या का शिकार हुए ईरानी वैज्ञानिक फखरीजादेह ने परमाणु हथियार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। गौरतलब है कि ईरान के दामावंद काउंटी के अबसार्द शहर में शुक्रवार को आधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह ईरान के रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र के प्रमुख थे।

ईरान का दावा, उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए

पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक फखरीजादेह गुप्त रूप से चलाए जा रहे ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। ईरान द्वारा हालांकि हमेशा से यह दावा किया गया है कि उसका परमाणु हथियार कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। फखरीजादेह की हत्या ऐसे समय में हुई है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन को लेकर चिंता जताई जा रही है।

'चांग ए-5' चांद की सतह पर सफलता पूर्वक उतरा

बीजिंग, (एजेंसी)। चीन का अंतरिक्ष यान 'चांग ए-5' ने मंगलवार को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक कदम रखा। चीन सेंट्रल टेलीविजन (सीसीटीवी) की रिपोर्ट के मुताबिक 'चांग ए-5' का 24 नवंबर को सफल प्रक्षेपण किया गया था। अंतरिक्ष यान को चांद की सतह से काफी मात्रा में सैंपल इकट्ठा करना चाहिए। इस मिशन के 23 दिन में पूरा होने के आसार हैं। ऐसा माना जा रहा कि इसमें लगा यंत्र दो किमी रेगोलिथ लेकर धरती पर वापसी करेगा। यह 44 वर्षों में पहला अंतरिक्ष यान है जिसे चांद की सतह से मिट्टी लाने भेजा गया है। चीन अगर मिशन में सफल रहा तो वह अमेरिका और रूस के बाद ऐसा कारनामा करने वाला तीसरा देश बन जाएगा।

भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से भी उलझा ड्रैगन, पीएम स्कॉट मॉरिसन ने लगाई लताड़

वेलिंग्टन, (एजेंसी)। चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य कई देशों के साथ भी उलझता रहता है। कभी सीमा विवाद को लेकर कोई नई चाल चलता है तो वहीं, कई बार फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा जाता है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक फोटो शेयर की, जिसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने फेक बताते हुए चीन से माफी की मांग की है। प्रवक्ता ने जो तस्वीर शेयर की थी, उसमें ऑस्ट्रेलियाई सैनिक एक बच्चे का गला रेतता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीनी अधिकारी की हरकत को पूरी तरह से घृणित बताया। उन्होंने चीन सरकार से माफी मांगने के लिए कहा है, लेकिन चीन ने इससे इंकार कर दिया। इस घटना के बाद पहले से ही चल रहा ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच विवाद और अधिक गहरा गया है। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान द्वारा शेयर की गई फोटो के बाद चीनी सरकार से माफी की मांग करते हैं।

झाओ ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कैप्शन

झाओ ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा था कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों द्वारा अफगान नागरिकों और कैदियों की हत्या से हैरान हूं। हम इस तरह के कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं, और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। वह इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित की गई रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे, जिसमें इस बात के प्रमाण मिले थे कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने अफगानिस्तान में संघर्ष के दौरान 39 अफगान कैदियों, किसानों और नागरिकों को मार डाला।

अभिनेता सलमान खान को मिली हाजरी माफी

जोधपुर, (एजेंसी)। फिल्म अभिनेता सलमान खान को बहुचर्चित हिरण शिकार मामले में मंगलवार को अदालत ने हाजरी माफी दे दी।

इस मामले में सलमान खान को मंगलवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन उनकी तरफ से वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हाजरी माफी पेश की गई है। इस पर अदालत ने हाजरी माफी स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई आगामी 16 जनवरी तय कर दी।

उल्लेखनीय है कि जोधपुर में काला हिरण शिकार मामले में वर्ष 2018 में सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू एवं सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।

कोलकाता में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मंगलवार को सोनागाछी (रेड लाइट एरिया) में दरबार महिला समिति द्वारा एक रैली निकाली गई।

कनाडा के पीएम की टिप्पणी पर भारत ने जताया एतराज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत ने कनाडा के नेताओं द्वारा किसानों से संबंधित मुद्दे पर की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं पर आधारित और अनुचित है।

भारत ने कहा कि बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाए। दरअसल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर कहा है कि उनका देश शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के अधिकार का हमेशा बचाव करेगा। गुरु नानक देव की 551वीं जयंती के मौके पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान कनाडा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने कहा कि यदि वह किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बारे में भारत से आने वाली खबरों को नजरअंदाज करते हैं तो वह कुछ चूक करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों का प्रदर्शन मंगलवार को लगातार छठे दिन भी जारी रहा। भारत सरकार ने प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को एक बैठक बुलाई है।

विकास दुबे केस — एसआईटी ने उत्तरप्रदेश सरकार को सौंपी 3100 पन्नों की जांच रिपोर्ट

150 करोड़ की संपत्ति की ईडी से जांच की सिफारिश

लखनऊ, (एजेंसी)। कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की सामूहिक हत्या की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी ने नौ बिंदुओं को आधार बनाकर 3100 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार की है। एसआईटी ने मास्टरमाइंड विकास दुबे द्वारा जुटाई गई 150 करोड़ की संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय से जांच की सिफारिश की है। दुबे गत 10 जुलाई को लखनऊ में विशेष कार्यबल (एसटीएफ) के साथ हुई कथित मुठभेड़ में मारा गया था।

अधिकारियों ने बताया कि अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अगुवाई में गठित तीन सदस्यीय एसआईटी ने गैंगस्टर द्वारा अवैध तरीके से हासिल की गई 150 करोड़ की संपत्ति की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गहराई से जांच कराने की सिफारिश की है। एसआईटी ने सरकार को सौंपी गई अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दुबे और उसके गैंग की मदद करने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए।

पुलिस पर बरसाई थी गोलियां

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुबे को मुखबिरी के चलते पहले से ही पुलिस की दबिश के बारे में जानकारी मिल गई थी। गत दो-तीन जुलाई की मध्यरात्रि कानपुर के बिकरू गांव में दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर गैंगस्टर के साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थीं, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी और एक थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मी मारे गए थे तथा पांच पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और एक आम नागरिक घायल हुआ था।

80 से अधिक पुलिस, अधिकारियों और कर्मियों को पाया दोषी

घटना की जांच के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय एसआईटी की जांच रिपोर्ट में 80 से अधिक पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों को दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के 700 पन्ने मुख्य हैं, जिनमें दोषी पाए अधिकारियों व कर्मियों की भूमिका के अलावा करीब 36 संस्तुतियां शामिल हैं। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 100 से ज्यादा गवाहियों के आधार पर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार की है। 12 जुलाई, 2020 को एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की, जो 20 अक्टूबर को पूरी हुई।

11 जुलाई को किया गया था एसआईटी का गठन

एसआईटी ने नौ बिंदुओं पर जांच को आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार की है। एसआईटी को 31 जुलाई को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी थी, लेकिन गवाहियों का आधार बढ़ने से यह 20 अक्टूबर को पूरी हो सकी। जांच में सामने आया है कि पुलिस के ही लोग विकास दुबे के लिए मुखबिरी करते थे और घटना की रात गैंगस्टर को पहले से मालूम था कि उसके घर पर पुलिस की छापेमारी होने वाली है। जांच में दुबे के घर पुलिस टीम के दबिश देने की सूचना पहले ही लीक कर देने से जुड़े कई तथ्य उजागर हुए हैं। दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद 11 जुलाई को एसआईटी का गठन किया गया था।

वक्फ संपत्तियां खरीदने-बेचने के खेल में फंसे पूर्व सांसद

प्रयागराज, (एजेंसी)। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों को मनमाने तरीके से बेचने के मामले में भी अतीक सीबीआई के रडार पर हैं। इस मामले में सीबीआई यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ दो एफआईआर पहले ही दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर चुकी है। इनमें से एक एफआईआर प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके के इमामबाड़े की बिल्डिंग को गिराकर वहां कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के मामले में दर्ज है।

इस इमामबाड़े को गिराने और वहां कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का मास्टर माइंड अतीक ही है। उन्होंने ही परदे के पीछे से पूरा गेम खेला था। उनके रसूख के चलते शिया समुदाय के विरोध के बावजूद इमामबाड़ा गिराकर वहां चौंसठ दुकानों का कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इस तोड़फोड़ में करोड़ों का खेल हुआ है। प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके की बताशा मंडी में दो सौ साल से पुराना इमामबाड़ा हैदर रजा स्थित है। यह शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। बाद में इसे गिराकर कामर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया

नैशनल हाईवे विभाग

पीएपी फ्लाईओवर 8 लेन पास होने से कुछ दूरी तक लोगों को सुविधा मिलेगी लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ेंगे अगले फ्लाईओवर 4 लेन होने के कारण लोगों को और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा ऐसी ही एक दुर्घटना सूर्य एन्क्लेव के फ्लाईओवर से पीएपी फ्लाईओवर को जाते हुए एक ट्रक और गाड़ी की आपस में टक्कर होने के कारण एक्सीडेंट हुआ पड़ा था जिस कारण नेशनल हाईवे पर लम्बा जाम लग गया क्यूंकि जब यह दुर्घटना हुई उसके बाद एक ही लेन लोगों के जाने के लिए बची रह गयी जिससे वहां घंटो तक जाम की स्थिति बनी रही।

पंजाब सरकार 1377 और स्कूलों को करेगी स्मार्ट स्कूलों में तबदील : विजय इंदर सिंगला

इन स्कूलों के डिजीटाईजेशन पर खर्च किए जाएंगे 357.34 करोड़ रुपए - शिक्षा मंत्री

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय इंदर सिंगला ने बुधवार को कहा कि जल्द ही पंजाब सरकार 1377 और स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील करने जा रही है और इन स्कूलों के डिजीटाईजेशन पर 357.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक 7,823 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली रा%य सरकार सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में निरंतर सुधार करके मानक शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के कुल 19130 सरकारी स्कूलों में से 41 प्रतिशत स्कूल पहले ही स्मार्ट स्कूलों में तबदील हो चुके हैं और उनकी सरकार ने अपने पाँच सालों के कार्यकाल में सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तबदील करने का लक्ष्य निश्चित किया है। श्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि कुल 1377 स्कूलों में से 817 ग्रामीण क्षेत्रों और 560 रा%य के शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, जहाँ शिक्षा विभाग ने क्रमवार 209.77 करोड़ रुपए और 147.56करोड़ रुपए ख़र्च करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में से 605 प्राथमिक स्कूल, 80 माध्यमिक, 159 हाई स्कूल और बाकी 533 सीनियर सेकंडरी स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि इन 1377 स्कूलों की नवीनीकरण प्रक्रिया इस वित्त

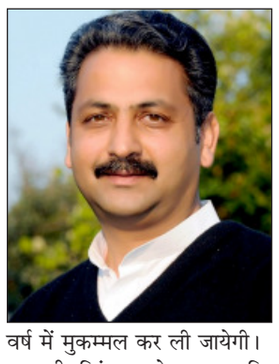

वर्ष में मुकम्मल कर ली जायेगी।

श्री सिंगला ने बताया कि अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान इन स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम, संगठित विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, ड्यूल डैस्क, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, पीने योग्य पानी की सुविधा, ऊँची चारदिवारियां, ग्रीन बोर्ड, प्रोजैक्टर, मिड-डे-मील के लिए खाना खाने वाली जगह और कलर कोडिंग जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के लिए ज़रुरी कामों के लिए विशेष मरम्मत और रख-रखाव का बजट भी रखा जायेगा।

कैबिनेट मंत्री ने कॉर्पोरेट कंपनियों, एन.जी.ओज़, कम्युनिटी नेताओं, पंचायतों, परोपकारी व्यक्तियों और स्कूल स्टाफ को भी अपील की कि वह स्कूलों के डिजीटाईजेशन के इस नेक कार्य के लिए योगदान दें और भावी पीढ़ीयों के बेहतर भविष्य के लिए खुले दिल से दान करें। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार अध्यापकों द्वारा तैयार की गई वीडीयोज़, ख़ान अकैडमी के लैक्चरों और टैलिविज़न के द्वारा ई-बुक्स, एज्यूसेट लैक्चर, ई-कंटैंट और ऑनलाइन क्लासों के ज़रिये सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के ढांचे को मज़बूत कर रही है।

श्री सिंगला ने कहा कि उनकी सरकार के यत्नों स्वरूप 2017 से सरकारी स्कूलों के नतीजों में निरंतर सुधार आया है और दाख़िले बढ़े हैं। स्कूलों का डिजीटलीकरण सरकारी स्कूलों के मानक को और ऊँचा उठाने में सहायता करेगा। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष तौर पर दिए गए योगदान के लिए स्कूल के अध्यापकों और अन्य स्टाफ का धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा, मिड-डे-मील और विद्यार्थियों को उनके घर जाकर किताबें बाँटने को यकीनी बनाया।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट की तरफ से पंजाब नवीनतम मिशन और फंड स्थापित करने को मंजूरी

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

राज्य में स्टार्ट-अप्प प्रणाली को उत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब इनोवेशन (नवीनतम) मिशन और पंजाब इनोवेशन फंड की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है।

पंजाब नवीनतम मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 150 करोड़ रुपए का एक पंजाब नवीनतम फंड स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे पंजाब में मूलभूत पड़ाव के स्टार्ट-अप्पस में निवेश किया जा सके। इस फंड में सरकारी हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा कुल रकम के 10 प्रतिशत भाव 15 करोड़ रुपए तक निश्चित गई है। इस फंड की संभाल एक अस्सेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा की जायेगी जिसमें वैश्विक स्तर के निवेशक शामिल होंगे। इस मिशन और फंड के पहले चेयरपरसन क्लिक्स कैपिटल के चेयरमैन और जैनपैकट के संस्थापक प्रमोद भसीण हैं। भसीण ने वर्चुअल ढंग के साथ हुई कैबिनेट मीटिंग के दौरान जानकारी दी कि वह बाकी की 135 करोड़ रुपए की रकम पंजाबी व्यापारियों और निवेशकों के अलावा विदेशों में बसते लोगों और सरकारी और निजी वित्तीय संस्थाओं से जुटाएंगे। सरकारी प्रवक्ता ने कैबिनेट मीटिंग के बाद में बताया कि पंजाब इनोवेशन मिशन राज्य में निवेशकों, उद्योग जगत, सरकारी, अकादमिक हलकों और स्टार्ट-अप्पस के साथ हिस्सेदारी और इसके अलावा विभिन्न इनक्यूबेटरों और ऐकसैलरेटरों के दरमियान सांझेदारी यकीनी बना कर, तकनीक, नीति और पूँजी की मदद से उद्यम समर्थकी एक अलग माहौल सृजन करने में अहम भूमिका निभाएगा। पंजाब इनोवेशन मिशन के दो अहम स्तंभ पौलीनेटर (विदेशों में बसते भाईचारे तक पहुँच, चुनौतियां/हैकाथौन, इनक्यूबेटर ट्रेनिंग जिसमें सभी सर्बाधित पक्ष और इनक्यूबेटर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे) और ऐकसैलरेटर (स्टार्ट-अप्पस सम्बन्धी नेतृत्व और इनको गतिशील बनाना) होंगे। हालाँकि, यह मिशन किसी एक क्षेत्र की तरफ समूचा ध्यान नहीं देगा परन्तु इसकी तरफ से ऐग्रीटैक, फूड

प्रोसेसिंग, हैल्थकेयर, फार्मा, बायोतकनालोजी, लाईफ सायंसिज, आई.टी./आई. टी. ई. एस., गेमिंग और खेल, कला और मनोरंजन की तरफ खास ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

सरकार की तरफ से पहले तीन वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपए का चालू खर्चा मुहैया करवा के पंजाब इनोवेशन मिशन और पंजाब इनोवेशन फंड का कामकाज चलाने में मदद की जायेगी। इस मिशन की स्थापना मोहाली में मंडी बोर्ड के कालकट भवन में से जायेगी, जहाँ दो मंजिलें (तकरीबन 12,000 स्कुएयर फीट) कम से -कम 15 वर्षों के लिए लंबे समय के पट्टे पर मुहैया करवाई जाएंगी जिनमें सभी आम सुविधाओं और सांझी जगह भी शामिल होंगी। पहले तीन वर्षों के लिए यह जगह मुफ्त मुहैया करवाई जायेगी। मिशन की गतिविधियों को उद्योग और वाणिज्य विभाग, इनवैस्ट पंजाब और पंजाब स्टेट कौंसिल फॉर साईंस एंड तकनोलोजी की तरफ से मदद दी जायेगी। पंजाब इनोवेशन फंड में निजी व्यक्तियों की हिस्सेदारी को उत्साहित करने के लिए रा%य सरकार ने अपनी आमदनी की सीमा 10 प्रतिशत तक तय/निधारित करने का फैसला किया है। सरकारी योगदान की इस 10 प्रतिशत सीमा से ज़्यादा की कमाई पंजाब इनोवेशन फंड में वापस चली जायेगी और जिसका इस्तेमाल फंड के चालू खर्चों की पूर्ति के लिए किया जायेगा। राज्य सरकार की तरफ से निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए फंड की मियाद बीतने के मौके पर पंजाब इनोवेशन फंड में निवेश करने वाले पहले पाँच निवेशकों के द्वारा निवेशित प्रमुख रकम के 20 प्रतिशत हिस्से गारंटी देने का फैसला किया है। इस गारंटी की अधिकतम कुल सीमा प्रति निवेशक 2 करोड़ रुपए निश्चित गई है और यह सरकार के लिए अधिक से अधिक संभावित 10 करोड़ रुपए की देनदारी में जुड़ेगी। सरकार के द्वारा यह कदम इस पक्ष को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया है कि इनोवेशन फंड द्वारा स्टार्ट-अप्पस में ऐसे निवेश खास तौर पर मूलभूत पड़ावों के दौरान बाजार की उथल-पुथल का शिकार हो सकते हैं।

खेल निदेशक द्वारा पंजाब प्रशिक्षक यूनियन के साथ मुलाक़ात

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब के खेल निदेशक श्री डी.पी.एस. खरबन्दा ने आज राज्य के अलग-अलग खेलों के प्रशिक्षकों को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार उनकी सभी जायज माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। निदेशक ने इस सम्बन्धी भरोसा आज मुलाकात के लिए पहुँचे पंजाब कोच यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान दिया। इस विचार-विमर्श के दौरान श्री खरबन्दा ने कहा कि राज्य सरकार, यूनियन की सभी जायज माँगों को मानने के लिए वचनबद्ध है।

विजीलैंस द्वारा नगर-निगम का सैनटरी इंस्पेक्टर 5000 रुपए रिश्वत लेता काबू

■ जालंधर/रवि

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम के दौरान आज नगर निगम अमृतसर में तैनात सैनटरी इंस्पेक्टर हरजिन्दर सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया जबकि वहीं एक अन्य मुलाजिम के खिलाफ भी केस दर्ज करके तलाश की जा रही है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दोषी हरजिन्दर सिंह को शिकायतकर्ता रिंकू कुमार, निवासी गेट भगतां वाला, अमृतसर की शिकायत पर विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से 5 हजार रुपए रिश्वत लेते काबू किया गया। प्रवक्ता ने बताया उक्त शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो को अपनी शिकायत में बताया कि वह नगर निगम अमृतसर में बतौर सफाई सेवक सेवाएं निभा रहा है। उक्त दोषी सैनटरी इंस्पेक्टर और उसका बिचोला विशाल गिल, जोकि वहीं सफाई सेवक है, की तरफ से उसकी बदली करवाने के बदले 10,000 रुपए की माँग की गई परन्तु सौदा 5000 रुपए में तय हुआ है। विजीलैंस की टीम की तरफ से दोषों की पड़ताल के उपरांत दो सरकारी गवाहों की हाजिरी में 5 हजार रुपए की रिश्वत के तौर पर लेते हुये सैनटरी इंस्पेक्टर हरजिन्दर सिंह को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी उक्त दोनों दोषियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना अमृतसर में मुकदमा दर्ज करके अगली कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

पंजाब कैबिनेट ने मोहाली में ऐमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने को दी मंजूरी

'दी ऐमिटी यूनिवर्सिटी ऑर्डीनैंस, 2020' के मसौदे को दी मंजूरी, पहला सैशन 2021 में होगा शुरू

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा बुधवार को मोहाली की आई.टी. सिटी में ऐमिटी एजुकेशन ग्रुप के विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी कैंपस को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही इस क्षेत्र का प्रमुख शिक्षा केन्द्र के तौर पर विकसित होने के लिए रास्ता साफ हो गया है।

यह फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।

पंजाब मंत्रालय ने 'दी ऐमिटी यूनिवर्सिटी ऑर्डीनैंस, 2020' को भी मंजूरी दे दी और मुख्यमंत्री को कानूनी सलाहकार द्वारा तैयार किये गए अंतिम मसौदे को बिना कैबिनेट में रखे मंजूर करने के लिए अधिकृत कर दिया।

मीटिंग के बाद सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पाँच सालों में 664.32 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मोहाली (एस.ए.एस. नगर) की प्रमुख स्थान पर 40 एकड़ क्षेत्रफल में सेल्फ फाईनांसड प्राईवेट 'ऐमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब' का स्थापित होने वाला अत्याधुनिक कैंपस उ%च स्तरीय अनुसंधान और नयी खोजों को उत्साहित करेगा। यह यूनिवर्सिटी अगले अकादमिक वर्ष से शुरू होगी जिसका पहला सैशन जून-जुलाई 2021 में शुरू होगा।

चण्डीगढ़/मोहाली हवाई अड्डे से केवल 10 मिनट की दूरी पर स्थापित होने वाली यह यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए उच्च मानक शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। यूनिवर्सिटी में सालाना 1500-2000 विद्यार्थियों के दाख़िले होंगे। उच्च स्तरीय अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग केंद्र के अलावा यूनिवर्सिटी यू.जी.सी. और पंजाब रा%य के दायरे के अंदर रोज़गार मुखी ग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट, पीएच.डी. और पोस्ट पीएच.डी. के अलग-अलग प्रोग्राम तैयार करेगी। नयी शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह सीमाओं से परे बहुउद्देश्यीय पहुँच को उत्साहित करेगी। मोहाली में मानक शिक्षा और इस क्षेत्र के सर्वपक्षीय विकास लाने की उम्मीद के साथ यह यूनिवर्सिटी ऐसी अनुशासनिक संस्था होगी जिसमें अलग-अलग विभाग जैसे कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर / आई.टी., कम्यूनिकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मनोविज्ञान, लिब्रल आर्ट, इंग्लिश लिटरेचर आदि होंगे।

ऑर्डीनैंस और नियमों व शर्तों के मुताबिक पंजाब सरकार ने इस स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी में पंजाब के विद्यार्थियों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया है। इसके साथ ही कुल संख्या के 5 प्रतिशत विद्यार्थियों को मुफ़्त शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अंतर्गत टीचिंग और नॉन-टीचिंग के अमले की भर्ती कर सकेगी।

ज़िक्रयोग्य है कि रा%य सरकार ने मानक ऊँच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'पंजाब प्राईवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी, 2010' तैयार की थी। इसी के अंतर्गत रितनन्द बलवेद एजुकेशन फाऊंडेशन, नयी दिल्ली द्वारा एस.ए.एस. नगर (मोहाली) की आई.टी.सिटी के सैक्टर-82 अल्फा के डी ब्लॉक में ऐमिटी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव सौंपा गया था। प्रस्ताव पर पॉलिसी के अनुसार विचार करते हुए उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 18फरवरी, 2020 को सम्बन्धित संस्था को सहमति पत्र जारी किया गया था।

मोहाली की यह दसवीं यूनिवर्सिटी होगी जो नॉन-प्रोफिट ऐमिटी एजुकेशन ग्रुप की तरफ से स्थापित की जायेगी। यह भारत के अग्रणी ग्लोबल शिक्षा ग्रुपों में से एक है जिसकी विश्व के 16मुल्कों में स्थापित 9 यूनिवर्सिटियाँ और 26स्कूल कैंपसों में 1,75,000 विद्यार्थी और 6000 फेकल्टी मैंबर हैं। पंजाब में विश्व स्तरीय संस्था स्थापित करने की वचनबद्धता के तौर पर ऐमिटी की तरफ से हाल ही में ऐमिटी इंटरनेशनल स्कूल, मोहाली और यह स्थापित की जाने वाली इस ऐमिटी यूनिवर्सिटी, मोहाली के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जायेगा।

कप्तान कोहली ने मैच में 23 रन बनाते ही वनडे में सबसे कम पारियों में 12000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है।

स्पोर्ट्स प्लैनट

टीम इंडिया तीसरा वनडे 13 रन से जीती

विदेशी जमीन पर लगातार 7 हार के बाद पहली जीत, सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम

■ कैनबरा/ब्यूरो

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को कैनबरा वनडे में 13 रन से हरा दिया। टीम इंडिया की विदेशी जमीन पर 7 हार के बाद यह पहली जीत है। इसी साल फरवरी में न्यूजीलैंड ने अपने घर में भारत को 3 वनडे और 2 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज के शुरुआती दो वनडे में भी हार मिली थी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 वनडे की सीरीज में 2-1 शिकस्त दी। कैनबरा वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 303 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 289 रन ही बना सकी। कप्तान एरॉन फिंच ने सबसे ज्यादा 75 और ग्लेन मैक्सवेल ने 59 रन की पारी खेली। फिंच की वनडे में यह 29वीं और मैक्सवेल की 22वीं फिफ्टी है।

सीरीज के आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सीरीज में पहली बार ओपनिंग करने आए मार्नस लाबुशाने 7 रन बनाकर टी नटराजन की बॉल पर बोल्ड हुए। नटराजन का डेब्यू मैच में यह पहला विकेट रहा। इसके बाद शार्दूल ठाकुर ने दो विकेट लिए। उन्होंने स्टीव स्मिथ (7) को विकेटकीपर लोकेश राहुल और मोइसेस हेनरिक्स (22) को शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराया। हेनरिक्स ने फिंच के साथ तीसरे विकेट के लिए 61 रन की पार्टनरशिप की।

पंड्या, जडेजा और कोहली की फिफ्टी

भारतीय पारी में कप्तान विराट कोहली, हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा ने फिफ्टी लगाई। पंड्या और जडेजा ने छठवें विकेट के लिए 150 रन की साझेदारी कर भारतीय पारी को संभाला। इस पार्टनरशिप के बदौलत टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवाकर 302 रन बनाए हैं। टीम के लिए पंड्या ने सबसे ज्यादा 92 और जडेजा ने 66 रन की नाबाद पारी खेली। कोहली ने 63 रन बनाते हुए वनडे करियर की 60वीं फिफ्टी लगाई। पंड्या की छठवीं और जडेजा की 13वीं फिफ्टी रही। ऑस्ट्रेलिया के लिए एश्टन एगर ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। एडम जम्पा, सीन एबॉट और जोश हेजलवुड को 1-1 विकेट मिला।

कैनबरा में भारतीय टीम पहला वनडे जीती, ऑस्ट्रेलिया पहली बार हारी

कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर ऑस्ट्रेलिया टीम पहली बार कोई वनडे हारी है। मैच से पहले टीम ने यहां 4 वनडे खेले थे और सभी जीते। जबकि भारतीय टीम इस मैदान पर पहली बार वनडे जीती है। इससे पहले टीम ने यहां 2 मुकाबले खेले थे और दोनों हारे।

हेड-टू-हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 143 वनडे खेले गए। इसमें टीम इंडिया ने 53 मैच जीते और 80 हारे हैं, जबकि 10 मुकाबले बेनतीजा रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में भारतीय टीम ने 54 वनडे खेले, जिसमें से 14 जीते और 38 मैच हारे हैं। 2 वनडे बेनतीजा रहे।

ओपनर धवन जल्दी पवेलियन लौटे

सीरीज में पहली बार भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर शुभमन गिल 33 और शिखर धवन 16 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन को एश्टन एगर ने LBW किया।

वहीं, धवन को सीन एबॉट ने एगर के हाथों कैच आउट कराया। शुभमन और कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 56 रन की पार्टनरशिप हुई।

मिडिल ऑर्डर फेल, 71 रन बनाने में 4 विकेट गंवाए

मैच में भारतीय मिडिल ऑर्डर फिर फेल रहा। टीम ने 15 से 32 ओवर के बीच सिर्फ 71 रन बनाए और 4 विकेट गंवा दिए। इस दौरान शुभमन गिल (33), श्रेयस अय्यर (19), लोकेश राहुल (5) और कोहली आउट हुए।

जडेजा-पंड्या ने 150 रन की पार्टनरशिप कर टीम को संभाला

152 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। ऐसे में पंड्या ने जडेजा के साथ छठवें विकेट के लिए 108 बॉल पर 150 रन की पार्टनरशिप कर टीम को संभाला और टीम का स्कोर 302 रन तक पहुंचाया।

कोहली ने वनडे में 50+ स्कोर के मामले में कैलिस की बराबरी की

भारतीय कप्तान कोहली ने सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने के मामले में साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस की बराबरी कर ली है। कोहली 103 बार यह स्कोर बनाकर कैलिस के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं। सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने के मामले में सचिन टॉप पर काबिज हैं। उन्होंने 145 बार ऐसा किया है।

कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

कप्तान कोहली ने मैच में 23 रन बनाते ही वनडे में सबसे कम पारियों में 12000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सचिन ने 309 मैच की 300 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था। जबकि कोहली ने 251 मैच की 242 पारियों में ही इस आंक? को छू लिया।

नटराजन का इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू

मैच के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए। मयंक अग्रवाल, नवदीप सैनी, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल को बाहर किया गया। उनकी जगह टी नटराजन, शुभमन गिल, शार्दूल ठाकुर और कुलदीप यादव को मौका मिला। नटराजन का इंटरनेशनल क्रिकेट में यह डेब्यू मैच है।

कैमरून ग्रीन का भी डेब्यू मैच

ऑस्ट्रेलिया टीम में 3 बदलाव किए थे। चोटिल डेविड वॉर्नर, मार्कस स्टोइनिस नहीं खेल रहे, जबकि पैट कमिंस को आराम दिया गया। उनकी जगह कैमरून ग्रीन, सीन एबॉट और एश्टन एगर को मौका दिया। ग्रीन का यह डेब्यू मैच रहा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor: ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.